दैनिक जागरण
सज्जनता का स्वभाव जीवन को सार्थक बनाता है

पाकिस्तान की शरारत

करतारपुर गलियारे को लेकर दूसरे दौर की बातचीत से पहले खालिस्तान समर्थक गोपाल सिंह चावला को पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बाहर किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत का दबाव रंग ला रहा है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि पाकिस्तान ने भारत को उकसाने के लिए ही गोपाल सिंह को करतारपुर गलियारे संबंधी समिति में शामिल किया था। भारत ने पाकिस्तान की इस हरकत पर न केवल कड़ी आपत्ति जताई थी, बल्कि करतारपुर गलियारे को लेकर होने वाली बातचीत भी रद कर दी थी। यदि पाकिस्तान ने यह हरकत न की होती तो करतारपुर गलियारे पर दूसरे दौर की बातचीत न जाने कब संपन्न हो जाती। वैसे गोपाल सिंह के निष्कासन के बाद भी इसकी उम्मीद कम है कि बातचीत सकारात्मक माहौल में होगी और करतारपुर गुरुद्वारे तक पहुंच आसान करने वाले इस गलियारे के निर्माण का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान ने गोपाल सिंह की खाली जगह एक अन्य खालिस्तानी समर्थक से भर दी है। यह एक तरह की शरारत ही है। पाकिस्तान के ऐसे हथकंडों को देखते हुए उचित यही है कि उसके इरादों को लेकर सतर्क रहा जाए। यह आशंका निराधार नहीं है कि पाकिस्तान इस गलियारे के जरिये खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा दे सकता है। यह किसी से छिपा नहीं कि भारत से सिख तीर्थ यात्री जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो वहां के गुरुद्वारों में खालिस्तानी तत्वों की सक्रियता बढ़ जाती है। ये तत्व भारत से गए श्रद्धालुओं को उकसाने और बहकाने की कोशिश करते हैं। गोपाल सिंह यही काम करता चला आ रहा है।

भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता कि पाकिस्तान न केवल अपनी धरती पर खालिस्तानी तत्वों को शह-समर्थन देता रहता है, बल्कि ब्रिटेन और कनाडा में भी ऐसे तत्वों की मदद करता है। ब्रिटेन और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की सक्रियता की एक वजह इन देशों की ओर से ऐसे तत्वों के प्रति बरती जाने वाली नरमी है। कनाडा सरकार ऐसे तत्वों के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम है और इसी कारण वहां ऐसे तत्व कहीं अधिक बेलगाम हैं। अभी हाल में भारत ने जिस चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर पाबंदी लगाई उसे मुख्यतः पाकिस्तान, ब्रिटेन और कनाडा में ही संरक्षण मिल रहा है। यह जरूरी है कि खालिस्तानी तत्वों के प्रति भारत ने जैसा कठोर रवैया पाकिस्तान के प्रति अपनाया वैसा ही कनाडा और ब्रिटेन के प्रति भी अपनाए। इसी के साथ करतारपुर गलियारे के निर्माण पर बातचीत आगे बढ़ाते समय वे सब प्रबंध भी करने होंगे जिससे पाकिस्तान इस गलियारे का दुरुपयोग न करने पाए। पाकिस्तान चाहे जो दावे करे, फिलहाल यही अधिक नजर आता है कि वह अपनी भारत विरोधी हरकतों का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। बेहतर होगा कि करतारपुर गलियारे पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान को यह संदेश देने में संकोच न किया जाए कि उसके साथ अन्य मसलों पर वार्ता की सूरत क्यों नहीं बन रही है? पाकिस्तान के प्रति तनिक भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। सच तो यह है कि उसे मुंबई और पठानकोट हमले के उन गुनहगारों की याद दिलाई जानी चाहिए जो उसके यहां छुट्टा घूम रहे हैं।

मुद्दों पर एकजुटता

कर्नाटक में चल रही सियासी उठापटक को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस, वाममोर्चा व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एकजुटता दिखाकर निंदा प्रस्ताव पारित किया था। इसके अगले ही दिन सांप्रदायिकता के खिलाफ कांग्रेस, वाममोर्चा और तृणमूल एकजुट दिखे और विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर नियम 185 के तहत वाममोर्चा, कांग्रेस तथा तृणमूल द्वारा लाए गए अलग-अलग प्रस्ताव पर बहस हुई, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, यानी भाजपा के खिलाफ विधानसभा में दो मुद्दे उठे तो तृणमूल, वाममोर्चा और कांग्रेस एकमत हो गए। पिछले दिनों जब विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वामो व कांग्रेस से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी तो वाममोर्चा व कांग्रेस ने कहा था कि वे तृणमूल के खिलाफ लड़ते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से सांप्रदायिकता व कर्नाटक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक तीनों ने एकजुटता दिखाई है, उसके राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। बंगाल में ममता पर भी वाममोर्चा और कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में अलग-अलग प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित होना महज सियासी हथकंडा कहा जा सकता है। इस बीच भाजपा विधायक दल के नेता मनोज तिग्गा ने कहा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री ने मस्जिद के इमामों के लिए भत्ता चालू कर सांप्रदायिकता की शुरुआत की। अगर राज्य में सांप्रदायिकता बढ़ी है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। यहां सवाल सांप्रदायिकता का था तो तृणमूल नेता भाजपा को सांप्रदायिक दल करार देते रहते हैं। वहीं वाममोर्चा और कांग्रेस बंगाल में भाजपा के साथ-साथ तृणमूल को भी सांप्रदायिक दल बताने से गुरेज नहीं करते हैं। दोनों दलों पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगते रहता है। खैर, सियासत में वोट बैंक और चुनावी स्वार्थ में सभी दल डूबे रहते हैं। ऐसे में अगर कुछ मुद्दों पर एकजुटता प्रदर्शित होना अच्छी बात है।

लगातार कमजोर होती कांग्रेस

संजय गुप्त

यह ठीक नहीं कि कांग्रेस राष्ट्रीय विपक्षी दल के रूप में कमजोर होने के बाद राज्यों में भी अपनी ताकत खोती जा रही है

कर्नाटक में सत्तारूढ़ गठबंधन का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर हैं जो उसे कांग्रेस और जद-एस विधायकों के इस्तीफे और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के रुख-रवैये को लेकर देना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, इसमें संदेह है कि कर्नाटक सरकार को कोई बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इस्तीफा देने वाले जद-एस और कांग्रेस के बागी विधायक अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अभी तक जिन 16 विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उनमें 13 कांग्रेस के हैं। दो निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। कांग्रेस नेतृत्व को इससे चिंतित होना चाहिए कि इस्तीफा देने वाले अधिकांश विधायक उसके ही हैं। यह विचित्र है कि कांग्रेसी नेता कर्नाटक और गोवा के घटनाक्रम को लेकर भाजपा के खिलाफ संसद में धरना-प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस की भाजपा से शिकायत समझ आती है, लेकिन आखिर इस सच की अनदेखी कैसे की जा सकती है कि उसके अपने ही विधायक पार्टी छोड़ने पर आमादा हैं? कांग्रेस के लिए यह किसी आघात से कम नहीं कि कर्नाटक का संकट सुलझता, उसके पहले ही गोवा में उसके विधायकों ने बगावत कर दी। गोवा के 15 में से 10 विधायक भाजपा से जा मिले। अब उनमें से कुछ सरकार में शामिल भी हो गए हैं।

गोवा का घटनाक्रम कांग्रेस के लिए नया झटका है, लेकिन ऐसे झटके उसे लगते ही चले आ रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात में उसके दो विधायकों ने बगावत कर दी थी। बगावत का यह सिलसिला कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व की कमजोरी को ही बयान करता है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस जिस तरह नेतृत्व के सवाल को लेकर उलझी हुई है उसका असर उसकी राज्य इकाइयों पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि नेतृत्व को लेकर असमंजस का जो दौर जारी है उससे आम कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर निराशा से घिर रहे हैं। हैरत नहीं कि इसी कारण पहले कर्नाटक के कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ना बेहतर समझा हो और फिर गोवा के कांग्रेसी विधायकों ने। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस में उठापटक जारी है। कुछ राज्यों में तो कांग्रेसी नेताओं की आपसी खींचतान पूरी तौर पर खुलकर बाहर आ गई है। कांग्रेस के पास अपनी राज्य इकाइयों की इस खींचतान को सुलझाने की फुर्सत इसलिए नहीं, क्योंकि वह खुद ही नेतृत्व के मसले को लेकर खींचतान से ग्रस्त है।

लोकसभा चुनाव के बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। करीब एक माह बाद राहुल गांधी ने त्यागपत्र देकर अपना इरादा और स्पष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी यह समझना कठिन है कि कांग्रेस की बागडोर कौन संभालेगा? पार्टी में नेतृत्व के मसले को लेकर कोई आम सहमति बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के बुजुर्ग नेता कुछ और चाह रहे हैं एवं युवा नेता कुछ और। यदि असमंजस का यह दौर और लंबा खिंचा तो कांग्रेस को और अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उसकी कुछ और राज्य इकाइयों में टूट-फूट हो सकती है। कांग्रेसी नेता बेहतर भविष्य की आस में दूसरे दलों की ओर रुख कर सकते हैं। कांग्रेस में असमंजस की स्थिति के लिए कहीं न कहीं गांधी परिवार भी जिम्मेदार है।

यह तो साफ है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते, लेकिन यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की क्या भूमिका होगी? भले ही राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव पद पर कायम हैं। उनका महासचिव पद पर कायम रहना इसलिए सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला था और प्रियंका को पूर्वी उत्तर प्रदेश का। दोनों ही नाकाम रहे, लेकिन इस्तीफा केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया।

कांग्रेस में एक ऐसे समय टूट-फूट जारी है जब इसकी जरूरत बार-बार दोहराई जा रही है कि देश को एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है। निःसंदेह इस आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। मौजूदा समय इस आवश्यकता की पूर्ति केवल कांग्रेस ही कर सकती है, क्योंकि वही एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद पूरे देश में व्यापक असर रखता है। आज देश में कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं जो राष्ट्रीय स्वरूप ले सके। इन स्थितियों में यह और आवश्यक हो जाता है कि कांग्रेस अपनी दिशा तलाशे और राजनीतिक सच्चाई को स्वीकार करे।

यह कहने से कांग्रेस का काम चलने वाला नहीं है कि भाजपा अपनी राजनीतिक ताकत और पैसे के बल पर विपक्ष को खत्म करने पर तुली हुई है। बेहतर हो कि कांग्रेस अपने राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रचित सेठ की उस बात पर गौर करे जो उन्होंने पद छोड़ते हुए कही थी। सेठ के मुताबिक भाजपा को दोष देने का कोई औचित्य नहीं, गड़बड़ियां हमारे अपने भीतर हैं। वह इस बात से भी हताश हैं कि 45 दिन बीत चुके हैं और नए कांग्रेस अध्यक्ष का चयन नहीं हो सका। स्पष्ट है कि कांग्रेस को अपनी रीति-नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि उसके कारण ही पार्टी में निराशा का माहौल है। निराशा का यह माहौल इसलिए और अधिक गहरा गया है, क्योंकि नेतृत्व का सवाल सुलझने के बजाय उलझता ही रहा है। इस उलझन के लिए कांग्रेस नेतृत्व अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकता।

कांग्रेस की यह सच्चाई है कि उसकी एकजुटता और प्रगति की धुरी गांधी परिवार ही है। इसीलिए कांग्रेस अब तक नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। यह ठीक है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले तक जब उन पर परिवारवाद के सहारे आगे बढ़ने का आरोप लगता था तो वह कहते थे कि उनके अंदर कांग्रेस का नेतृत्व करने की काबिलियत है। अब जब पार्टी संकट में है तो वह मोर्चे से हटना चाहते हैं। हालांकि यह भी प्रतीत हो रहा है कि वह पर्दे के पीछे से सक्रिय रहकर पार्टी को यह अहसास भी कराना चाहते हैं कि उनकी आवश्यकता है। ऐसे में सवाल यह उभरता है कि क्या राहुल गांधी अपने त्यागपत्र के जरिये उन कांग्रेस नेताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं जिन्होंने कथित रूप से पार्टी से ज्यादा अपने हितों को तरजीह दी। कुल मिलाकर कांग्रेस का नेतृत्व गांधी परिवार का आंतरिक मामला ही है-खासकर तब जब सोनिया गांधी नेतृत्व के सवाल पर पीछे हट चुकी हैं। यह कांग्रेस और साथ ही देश की राजनीति के हित में है कि गांधी परिवार इस संकट का तत्परता से समाधान करे।

अवधेश राजपूत

response@jagran.com

सावधान, आगे खतरनाक इमारत है

हास्य-व्यंग्य

ज्ञान चतुर्वेदी

अब पूरी इमारत हवा में है। नियम-कायदे की एक ईंट भी नहीं। बातों की ईंटें। बयानों का चूना। बिना छत का भवन

देश के अहाते में सालों से खड़ी एक इमारत अब ध्वस्त सी हो गई है। हम उसी में रह रहे हैं। पर करें क्या? कहां जाएं? व्यवस्था का यह भवन जर्जर हो गया है। पलस्तर झड़ रहा है। कहीं से गुजरो, सिर पर धूल गिरती है। कायदों का सीमेंट टूटकर गिर रहा है। नागरिक के सिर पर कायदे गिर रहे हैं। कभी शिकायत करो तो कहते हैं कि तुम कतई चिंता मत करो। 'अरे, इसकी नींव बड़ी मजबूत है। छत गिर भी जाए, पर नींव बचा ले जाएगी तुम्हें। कमाल की नींव रखकर गए हैं इमारत बनाने वाले।' संविधान की इस नींव पर बड़ा नाज है इमारत के मालिकों को। इमारत बड़ी अजीब हो गई है। मजबूत नींव। ढीले-ढाले नियमों का ईंट-गारा। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। भाई से ईंट, भतीजे से रोड़ा। फाइलों की रेत, अफसरी का चूना। नियमों की छत हर जगह से टपकती है। चुनाव का पानी बरसता तो पांच वर्षों में बस एक बार है, पर राजनीति के बरसाती पानी के निकास की कोई भी व्यवस्था पूरी इमारत में बनाई ही नहीं गई है।

इमारत का कोना-कोना रिसता है। चारों तरफ राजनीति की सीलन का कब्जा है। सिफारिशों के जाले हर कोने में हैं। चापलूसी की फफूंद। ईंटें हिल रही हैं। सब तरफ दरारें हैं। कहने को इमारत की मरम्मत का काम भी अहर्निश जारी है। रंग-रोगन लगातार चलता रहता है। बिल बनते हैं। बिल पास होते हैं। दौरे। निरीक्षण। तबादले। जांचें। पोस्टिंग। वार्निंग। सस्पेंड। बर्खास्त। कंपल्सरी रिटायरमेंट। शपथ। बड़े साहब। उनसे भी बड़े साहब। छोटे साहब। उनसे भी छोटे साहब। सब साहब हैं। सब तरफ साहबी है। पलस्तर पर पलस्तर। रंग पर नया रंग। दरारें पुरती नहीं। दरवाजे ढीले हैं। खिड़कियां गायब। सरिये उखड़ रहे हैं। सही बात तो यह है कि पूरी इमारत ही ध्वस्त हो गई है। देश इसी इमारत में रहने को अभिशप्त भी है। देश डरा-डरा रहता है इसके नीचे। देश को इस व्यवस्था पर मानो भरोसा ही नहीं रहा। हर सहारे पर शक हो चला है। सीढ़ियां कहीं पहुंचाती नहीं। नालियां चोक हैं। नल या तो बंद हैं या उनकी टोंटियां गायब हैं। तो फिर इसे खतरनाक घोषित क्यों नहीं करते? इसे ठीक क्यों नहीं करते? गिरा क्यों नहीं देते? जर्जर इमारतों को खतरनाक घोषित कर गिराने की व्यवस्था है संविधान में। एक राजनीतिक प्रणाली काम पर है। फिर गिराते क्यों नहीं। गिराने के टोटके भर चलते हैं। इसे गिराने की व्यवस्था जिन्हें करनी है वे कीचड़ की बाल्टियां और क्रिकेट का बल्ला लेकर गिराने निकले हैं। नारा लगाकर, शहर में पोस्टर चिपकवाकर, वे इस इमारत को देश के सिर पर ही गिराने की कोशिश में हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं?

क्योंकि उन्होंने स्वयं एक ऐसी इमारत बनाई है। वह भी इसी अहाते में है। राजनीति की इनकी इमारत व्यवस्था की इमारत से भी खतरनाक है। इनकी इमारत तो बिना नींव की है। वैसे कभी इसकी मजबूत सी नींव भी थी। स्वतंत्रता आंदोलन की गहरी नींव। इन्होंने उसे उतना ही गहरा खोद डाला। अब पूरी इमारत हवा में है। नियम कायदे की एक ईंट भी नहीं। बातों की ईंटें। बयानों का चूना। बिना छत का भवन। चूहों का कब्जा है पूरी इमारत पर। चूहे भी ऐसे कि बिल्लियों को पाल लिया है इन चूहों ने। चूहे बेखौफ हैं अब। बिल्लियां चूहों की सुरक्षा कर रही हैं। पालतू बिल्लियों को दूध मिल रहा है। बिल्लियां खुश हैं। वे चूहों की प्रशस्ति गा रही हैं। देश ऐसे में क्या करे? इन इमारतों का क्या करे? गिरा दे तो रहे कहां? दोनों इमारतें एक ही अहाते में है। एक सी खतरनाक। राजनीति की इमारत ज्यादा खतरनाक है या प्रशासन की? वैसे, दोनों ही एक जैसी डरावनी हो गई हैं। कहीं दोनों इमारतें एक दूजे का एक्सटेंशन तो नहीं हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि, दोनों इमारतें कई जगह पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वही गलियारे हैं। सुरंगें हैं। दोनों के बीच विश्वस्त चोर दरवाजे हैं। दोनों एक सी लगती हैं। दोनों एक ही हैं। पूरे अहाते को ही खतरनाक बना दिया है इन इमारतों ने। फिर क्या हो?

नागरिक इन इमारतों में रहने को मजबूर हैं। सब चाहते हैं कि ये इमारतें खतरनाक घोषित हों। पर जो तीसरी इमारत इन्हें खतरनाक घोषित कर सकती है, दरारें उसमें भी आने लगी हैं। यह है न्याय की इमारत। इससे पहले कि पूरा अहाता ही खतरनाक हो जाए कुछ तो करना होगा। बल्ले या कीचड़ की बाल्टी को जो लोग औजार मान बैठे हैं, वे भोले हैं, अपराधी हैं या नितांत गैरजिम्मेदार-वे हैं इन्हीं इमारतों के मालिकों की औलाद। अब तो अहाते के मालिकों को ही कुछ करना होगा। पहले तो उन्हें समझना होगा कि असली मालिक वे ही हैं। जमीन उनकी है। ये मालिक लोग सुन रहे हैं न? नागरिक बहरे तो नहीं हो रहे? सुन रहे हों तो अहाते को बचाने बाहर निकलें।

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद की अनुभूति

मनुष्य जीवन में आनंद का भाव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी आनंद की खोज में प्रत्येक मनुष्य जीवनपर्यंत कुछ भी करने के लिए आतुर रहता है। फिर भी बहुधा यह देखने को मिलता है कि मनुष्य जितना आनंद के पीछे भागता है, आनंद भी उससे उतनी ही दूरी बनाकर रहता है। कोई समृद्ध और पूर्ण रूप से संपन्न है तो इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि उसका जीवन भी आनंदित हो। आनंद के भाव पर हमारे शास्त्रों में भी बहुत चर्चा हुई है। तैत्तिरीयोपनिषद् में लिखा है, 'हम आनंद से आए हैं, आनंद के लिए जीते हैं और उसी पवित्र आनंद में एक दिन घुल जाएंगे।' द्वैत के इस संसार में जहां हम अपने आसपास इतनी पीड़ा और क्लेश देखते हैं। जहां लोग छोटी-बड़ी परेशानियों से जीवन को बोझिल मानने लगते हैं वहां यह कथन यथार्थ से इतर प्रतीत हो सकता है। पूरक प्रश्न भी उठ सकता है कि 'यदि मेरे परिवेश में इतना दर्द, इतना कष्ट है तो ऐसा कैसे संभव है कि मैं आनंद से आया हूं, आनंद में जी रहा हूं और एक दिन इसी आनंद में विलीन हो जाऊंगा।'

संभव है कि प्रायः जीवन में ऐसा कोई विचार भी मन को आहत करे, परंतु एक उपनिषद के शब्दों को साधारण नहीं समझा जा सकता। अवश्य ही उसके पीछे कोई न कोई असाधारण संकल्पना रही होगी। बौद्धिक स्तर पर चाहे हम इस कथन के पूरे अर्थ को ग्रहण न भी कर पाएं तो एक आस्था और उससे जुड़ी उम्मीद तो बनी रहती है। अगर हम पुरातन ऋषियों द्वारा प्रवर्तित शाश्वत नियमों का पालन करें तो हम इस कथन में निहित सत्य का दर्शन कर सकते हैं। तब आनंद की भावना हमारे निकट आ सकती है।

हमारा जीवन जितना प्रतिस्पर्धी, भौतिकतावादी और अनिश्चित होता जा रहा है तो हमारे भीतर व्यग्रता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। यही व्यग्रता आनंद को लील रही है। जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर हर कोई इसी पहेली से जूझ रहा है कि अब आगे क्या होगा? समाज में जैसे व्यग्रता बढ़ेगी तो उससे चिंता और अन्य उद्वेग उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है। यदि हम योग-ध्यान का अभ्यास कर स्वयं को मानसिक रूप से सबल बनाएं तो बहुत लाभ होगा। इससे हम बाहर से व्यस्त (कर्तव्यशील) और भीतर से मस्त (अपने ज्ञान में आश्वस्त) रह सकते हैं। जीवन में तमाम समस्याओं के बावजूद यह कड़ी हमें आनंद की अनुभूति करा सकती है।

श्री श्री परमहंस योगानंद

तथ्य-कथ्य | क्रिकेट विश्व कप मैचों में सबसे ज्यादा रन बचाने वाले फील्डर

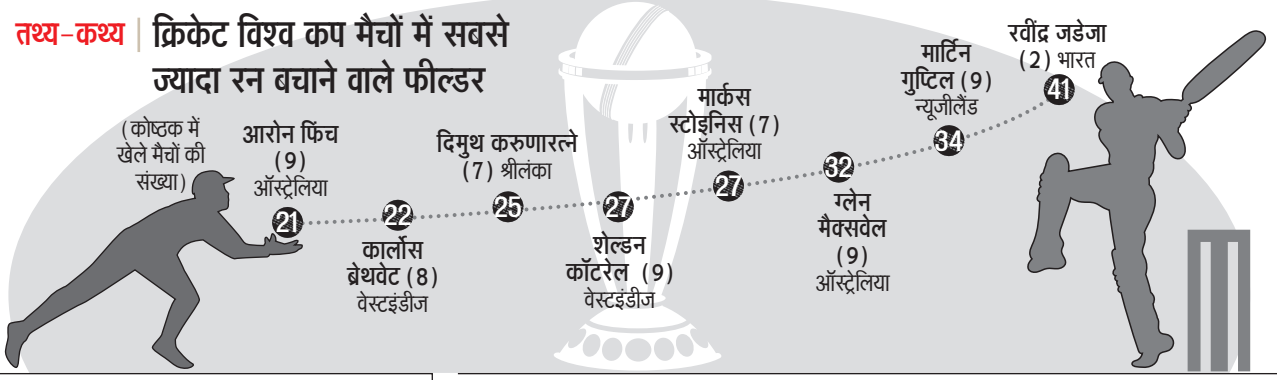

चांद को छूने वाला नायाब मिशन

गुकुल व्यास

चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा। ऐसे में हमारा चंद्रयान-2 मिशन कई मायनों में खास बनने जा रहा है

सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एक बड़ी छलांग लगाने वाला है। भारत का शक्तिशाली भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, जीएसएलवी-मार्क 3 चंद्रयान-2 को लेकर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। यह यान अपने साथ एक लैंडर और एक रोवर भी ले जाएगा। लैंडर का नाम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर 'विक्रम' रखा गया है। रोवर एक छह पहियों वाली चंद्र गाड़ी है जिसका नाम 'प्रज्ञान' नाम रखा गया है।

चंद्रयान-2 इसरो का बेहद महत्वाकांक्षी मिशन है। इससे पहले भारत ने अक्टूबर 2008 में चंद्रयान-1 को चंद्रमा पर 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया था। इसरो के इतिहास में चंद्रयान-2 सबसे चुनौतीपूर्ण और तकनीकी दृष्टि से अत्यंत जटिल मिशन है, क्योंकि इसरो न सिर्फ मुख्य परिक्रमा-यान (ऑर्बिटर) को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करेगा, बल्कि चंद्रमा की मिट्टी पर लैंडर को बहुत हल्के ढंग से उतारेगा। रोवर से युक्त लैंडर ऑर्बिटर से अलग होने के बाद छह या सात सितंबर को धीरे-धीरे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इस तरह चंद्रयान-2 को पृथ्वी से चंद्रमा की सतह तक 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में 53 से 54 दिन लगेंगे। सबसे खास बात यह है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश होगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने भी वहां यान उतारने की कोशिश नहीं की है। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की सतह को छूने में 15 मिनट लगेंगे। लैंडर में लगे हुए सेंसर यान को चट्टानों और क्रेटरों से बचाते हुए सही जगह पर उतरने में मदद करेंगे। सतह पर उतरने के करीब साढ़े चार घंटे बाद लैंडर से रोवर बाहर निकल कर चंद्रमा की सतह पर प्रयोग शुरू कर देगी।

चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर में कुल 14 उपकरण हैं जो चंद्रमा की तस्वीरें खींचेंगे तथा खनिजों, हीलियम गैस और भूमिगत बर्फ की तलाश करेंगे। लैंडर और रोवर को बेंगलुरु स्थित लूनर टेरेन टेस्ट फेसिलिटी में चंद्रमा जैसी सतह पर भली-भांति परखा जा चुका है। यहां चंद्रमा जैसी सतह के निर्माण के लिए तमिलनाडु के सलेम से लाई गई एक खास प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया गया है।

पहले अमेरिका से चंद्रमा जैसी मिट्टी मंगाने पर विचार किया गया था जिसका मूल्य 150 डॉलर प्रति किलो था। इसके लिए 60 -70 टन मिट्टी की जरूरत थी। इसरो ने महंगी मिट्टी आयात करने के बजाय स्थानीय समाधान खोजना ही बेहतर समझा। इसरो के अध्यक्ष के. शिवन का कहना है कि ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 मिनट का सबसे अहम हिस्सा होगा। ये बहुत डरावने क्षण होंगे। लैंडर के नीचे उतरते हुए रफ्तार को नियंत्रित करने वाले इंजन इसरो की एक बड़ी तकनीकी सफलता है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारतीय मिशन से नई वैज्ञानिक जानकारियों की उम्मीद की जा सकती है। चंद्रयान-2 मिशन को साकार करने में दो महिला वैज्ञानिकों का भी अहम योगदान है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

आपरेशन तोड़फोड़

भाजपा अक्सर कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती आई है। इसका मकसद एक तरह से राजनीति की मुख्यधारा में विपक्ष को चारों खाने चित कर देना है। कर्नाटक और उसके बाद गोवा में भाजपा की रणनीतिक चालों से पस्त कांग्रेस में सिरहन होना स्वाभाविक है। इन दो राज्यों के अनुभव के बाद पार्टी अब अपने सांसदों को लेकर बेहद सतर्क हो गई है। खासकर अपने राज्यसभा सांसदों को लेकर पार्टी की चिंता कुछ ज्यादा ही होने लगी है, क्योंकि भाजपा इस सदन में बहुमत से अभी कुछ पीछे है। इसीलिए पार्टी रणनीतिकारों को ऐसे सांसदों से निरंतर संवाद रखने के साथ उनकी सियासी गतिविधियों पर भी निगाह रखने को कहा गया है। गोवा में जिस तरह भाजपा ने विपक्ष के नेता समेत कांग्रेस के दो तिहाई विधायकों को सत्ता सुख का चारा डालकर तोड़ लिया। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों को लेकर पार्टी की चिंता वाजिब है। वैसे भी तेलुगु देसम पार्टी के चार राज्यसभा सांसदों को तोड़ भाजपा में शामिल कराने का ताजा उदाहरण कांग्रेस के सामने है। हालांकि राज्यसभा में कांग्रेस को तोड़ना आसान नहीं, मगर गोवा प्रकरण को विपक्ष के अस्तित्व को ही खत्म करने का भाजपा का प्रयास मान रही कांग्रेस सांसदों को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसीलिए राज्यसभा सांसदों पर निगाह रखने के साथ हर सप्ताह मंगलवार को लोकसभा के सांसदों की बैठक बुलाने का फैसला किया गया है। अब तो यह वक्त ही बताएगा कि सांसदों को भाजपा से बचाने का कांग्रेस का फूल-प्रूफ इंतजाम कितना कारगर साबित होता है।

मंत्री जी का कविता प्रेम

संसद में चलने वाली चर्चाओं और बहस में कविताओं और शेरो-शायरी वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बात अगर सरकार के मंत्री रामदास अठावले से जुडी हो तो बात कुछ और होती है। वैसे भी उनका कविताओं को पढ़ने का कुछ ऐसा चुटीला अंदाज ही है कि हर कोई उनकी कविताओं पर ठहाके लगाता दिखता है। हाल में राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अठावले को लेकर कुछ ऐसा ही आकर्षण देखने को मिला। चर्चा के लिए जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, बाकी सदस्यों के चेहरे पर मुस्कराहट खुद-ब-खुद तैरने लगी। आखिर में कई सदस्यों ने उनसे कोई नई कविता की जगह बजट पर ही बोलने का आग्रह किया। पर बगैर कविताओं के मंत्री जी बात कहां पूरी होने वाली थी। सो मंत्री जी ने खड़े होते ही अपनी चर्चा की शुरुआत कविता से ही की। फिर क्या, पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा।

अधिकारियों की मुश्किल

जब से वित्त मंत्रालय में पत्रकारों के लिए पहले से समय लेकर अधिकारियों से मिलने का आदेश जारी हुआ है, दूसरे मंत्रालयों के अधिकारियों की दिक्कत बढ़ गई है। इन मंत्रालयों के अधिकांश अधिकारी पत्रकारों से मिलने में कतराने लगे हैं। मिलना तो दूर अब इन अधिकारियों ने सभी पत्रकारों के फोन लेना भी बंद कर दिया है। केवल उन्हीं लोगों से फोन पर बात हो रही है जिनके साथ संबंध काफी पुराने या गहरे हैं। इसके चलते अब अधिकारी अपाइंटमेंट देने को भी तैयार नहीं हैं। जो अधिकारी मिल भी रहे हैं वे हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी जानकारी मुंह से न निकल जाए जो उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दे। ऐसे में अब ज्यादातर मंत्रालयों में मंत्रियों के निजी स्टाफ के पास जाने वालों की संख्या बढ़ रही है।

मेहनत से भी चोरी

सत्ता से बाहर आने के बाद भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इसका नशा टूट नहीं रहा है। बिना कुछ मेहनत के ही वे सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा हाल में कांग्रेस के एक विरोध प्रदर्शन और पैदल मार्च में देखने को मिला। सुब्रमण्यम स्वामी के एक बयान को लेकर इस सप्ताह कांग्रेस ने अपने मुख्यालय 24 अकबर रोड से स्वामी के घर तक विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया। मार्च के लिए पुलिस का बंदोबस्त भी था। कांग्रेसी नेताओं को लग रहा था कि मार्च शुरू होने के कुछ देर बाद पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक लेगी, लेकिन आश्चर्यजनक यह रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने कांग्रेस के इस मार्च को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। नतीजा यह हुआ कि पांच-दस मिनट में ही कांग्रेसी नेता हैरान-बेहाल हो गए। उनमें से कुछ तो वहां मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों के पास जा पहुंचे और उनसे मार्च रो